the report. Till now, the number of samples examined is 1760 and adulteration is found in 472 samples and the percentage is 26.81.

Sir, the number of prosecutions in 1999 was 5114 and the number of cases decided by courts was 2935; 1214 persons were convicted and 1721 were acquitted. In 2000, the number of prosecutions was 4532; the number of cases decided by courts was 2373; 789 persons were convicted and 1584 were acquitted. In 2001, the number of prosecutions was 5943, the number of cases decided by courts was 2704; 1263 persons were convicted and 1441 were acquitted. In 2002, the number of prosecutions was 2867 and...

MR. CHAIRMAN: You lay this statement on the Table of the House.

Opening of hospitals on the pattern of AIIMS

*64. SHRIMATI VANGA GEETHA:†
PROF. M.M. AGARWAL:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether six more institutes like AIIMS are being planned to be set up in backward areas;

(b) if so, the details of the places selected and progress achieved in this regard;

(c) the details of the funds allotted, released and actually utilized on the construction of these hospitals during the year 2003-04 and till date;

(d) the details of facilities alongwith the total beds to be provided by the above hospitals; and

(e) by when, the above hospitals are likely to be commissioned?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMDOSS): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Last year, a scheme called Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojna was formulated wherein it was decided in-principle to set up one AIIMS-type institution each in the States of Bihar (Patna), Chhattisgarh (Raipur), Madhya Pradesh (Bhopal), Orissa (Bhubaneshwar), Rajasthan

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Vanga Geetha.

(Jodhpur) and Uttaranchal (Rishikesh). These States were chosen as they were under served in terms of medical infrastructure, high incidence of mortality and mobidity, inadequate facilities for superspeciality services etc. Under the scheme, it is also proposed to upgrade one medical college each in the States of Andhra Pradesh, Jharkhand, Jammu & Kashmir, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal to the level of proposed AIIMS like institutions.

Planning Commission has accorded in-principle approval for an estimated amount of Rs. 4158 crores towards the scheme. The scheme is currently in the process of being placed before the Expenditure Finance Committee.

Land for the proposed AIIMS type institutions has been handed over to Hospital Services Consultancy Corporation (HSCC) (I) Ltd. in four States (Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Orissa and Uttaranchal) and the construction of boundary wall around these sites is underway. The process of transfer of land to HSCC in Patna and Jodhpur is being actively pursued with the respective State Governments. The process for selection of Project Consultant for providing comprehensive Consultancy services and selection of prototype architectural concept/design for AIIMS like institutions has been started.

During the financial year 2003-2004, Rs. 6 crores were provided for the Project. During the current financial year 2004-05, Rs. 60 crores have been provided. Rs. 6 crores have been released to Hospital Services Consultancy Corporation (India) Ltd. as an advance for the construction of the boundary wall at the sites of the proposed six AIIMS.

It has been envisaged that each Institute will have 500 beds for providing Medical treatment in 35 speciality/super speciality disciplines.In addition, there will be additional beds for superspecialities. It would also provide under graduate medical education with 100 intake capacity per year and PG/doctoral courses in various speciality/super speciality discipline with admission capacity as per MCI norms. The hospitals are expected to become operational after three years from the date of commencement of construction.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, I want to know from the hon. Minister as to why there is no mention about Andhra Pradesh in his reply. Sir, it is a fact that the then hon. Minister of Health and Family Welfare

had accepted the proposal of the former Chief Minister to upgrade NIMS to the status of AIIMS. She had also agreed to release Rs. 100 crores immediately. The State Government had even provided the land.

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, this project of building six new institutes like AIIMS and upgrading the existing hospitals to the level of AIIMS was envisaged last year. Now, we are waiting for the EFC. After the outcome of the EFC, we will decide on it.

प्रो॰ एम॰ एम॰ अग्रवाल: स्भापति महोदय, आप भी जानते हैं कि शहरों में तो बीमारियों का कुछ न कुछ इलाज हो ही जाता है लेकिन गांवों में इलाज का कोई प्रबंध नहीं है। जो हमारी सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं हेल्थ सेक्टर के माध्यम से, वे शिथिल पड़ी हुई हैं और काम नहीं हो रहा है। जो बीमारियां खत्म हो गई थीं, वे फिर से आ गई हैं। टी॰बी॰ पहले खत्म हो चुकी थी, दोबारा आ गई। पिछली मिनिस्ट्री में यह तय हुआ था कि डॉट से...

श्री सभापति: यह ऐम्स का क्वेश्चन है।

प्रो॰ एम॰ एम॰ अग्रवाल: ऐम्स का नहीं साहब, मैं दूसरा सप्लीमेंटरी पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: आप ऐम्स का ही पूछ सकते हैं।

प्रो॰ एम॰ एम॰ अग्रवाल: मैं केवल दो सवाल करूंगा।

श्री सभापति: कौन सा सवाल?

प्रो॰ एम॰ एम॰ अग्रवाल: क्या मैं सेकेंड सप्लीमेंटरी नहीं करूंगा?

कुछ माननीय सदस्य: नहीं, आप सेकेंड सप्लीमेंटरी नहीं कर सकते।

श्री सभापति: आप एक ही सवाल कर सकते हैं।

प्रो॰ एम॰ एम॰ अग्रवाल: एक ही क्यों? ...अच्छा, चलिए ऐम्स का ही सवाल पूछता हूं। ऐम्स के बारे में मुझे यह कहना है कि 6 स्टेट्स में ऐम्स बनाया जा रहा है और अभी तक कुल 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वह 6 करोड़ तो कंसल्टेंसी की फीस हो गई और 60 करोड़ का और प्रावधान किया गया है, जिसके लिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसमें अब तक उन्होंने क्या किया है? क्या कोई ज़मीन उपलब्ध कराई है या नहीं और कब तक ये 6 ऐम्स बनेंगे?

श्री सभापति: ऑनरेबल मिनिस्टर बोलिए।

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, regarding the setting up of six more institutes like AIIMS, last year, an allocation of Rs. 6 crores was made in the Budget, and about Rs. 2.4 crores were spent to build the compound wall. Sir, for these six places, the State Governments had to given in a minimum of 100 acres of land, and they were also supposed to take care

of road, water and electricity. Until now we have got land from four States. Excepting Bihar and Rajasthan, we have got land from Madhya Pradesh, Orissa, Uttaranchal and Chhattisgarh. And, this year, a Budget allocation of Rs. 60 crores has been made. But, Sir, the process of EFC is still going on, and after the outcome of the EFC, we will decide on it.

प्रो॰एम॰एम॰ अग्रवाल: साहब, इसका कुछ निष्कर्ष निकला है क्या?

श्री सभापति: निष्कर्ष तो इसका बहुत निकाल लिया। 60 करोड़ का बजट रखा है देख लीजिए। श्रीमती सुषमा स्वराज, पूछिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, देश में 6 नए ऐम्स बनाने की योजना देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल के रूप में जानी गई है। आप स्वयं इससे जुड़े रहे हैं। ऐम्स, पटना का शिलान्यास आपके कर-कमलों के द्वारा हुआ था। मंत्री जी के अपने स्टेटमेंट के मुताबिक यह योजना लगभग 4158 करोड़ रुपए की है। सभापति जी, मैं आपका ध्यान इसमें चाहूंगी कि यह योजना लगभग 4158 करोड़ रुपए की है और मंत्री जी के अपने बयान के मुताबिक निर्माण कार्य शुरू होने के तीन साल के अंदर-अंदर इनको चालू होना है और केवल 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो आपने अभी कहा 60 करोड़ -यह वह राशि है जो अंतरिम बजट में पिछली सरकार के वित्त मंत्री ने रखी थी। कल के बजट में हम खोजते रह गए, एक रुपया भी उन्होंने उसमें नहीं बढ़ाया। Not a single penny, एक रुपया, एक आना, एक पाई का प्रावधान इसमें 60 करोड़ के ऊपर अतिरिक्त नहीं किया गया है। तीन साल के अंदर जो 4158 करोड़ रुपए की योजना से बनने वाले 6 ऐम्स हैं, उसके लिए 60 करोड़ रुपया - अगर इस तरह से योजना चलेगी तो फिर कितने वर्ष इसको बनने में लगेंगे?

मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहती हूं कि हमने पिछली बार एक हजार करोड़ रुपए की राशि का इस बजट में प्रावधान करने की बात कही थी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या वर्तमान वित्त मंत्री जी से वे वही एक हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रिवाइज्ड एस्टिमेट में ही चाहे चाहें, करवाएंगे और इसी वर्ष इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Mr. Chairman, Sir, as I said earlier, this project was envisaged last year, and they had not, in principle, taken the approval of the Planning Commission. This year only, the EFC is going on, and we are yet to go to the Cabinet for its approval. After doing that, we will take up the question of increasing the budget allocations.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, जब बजट बन रहा था तो यह प्रोसेस पहले कम्पलीट क्यों नहीं किया। बजट से पहले ईएफसी होती है या बजट के बाद ईएफसी होती है? 60 करोड़ प्लानिंग

कमीशन का इन प्रिंसिपल आपको एप्रूवल मिल चुका है। सर, ईएफसी होने के बाद हम लोगों ने पैसा मांगा था। बजट से पहले ईएफसी होती है या बजट के बाद ईएफसी होती है। ... (व्यवधान)...सर, यह 60 करोड़ रुपया तो इनटेरिम बजट में रख दिया गया था। इनटेरिम बजट से एक रुपया भी नहीं बढ़ा। Not a single penny has been increased. ...(व्यवधान) ... 60 करोड़ रुपया तो इनटेरिम बजट में रखा गया था। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: यह बात तो आप बजट-स्पीच में बोल सकती हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: बजट की स्पीच में क्यों बोलूं, सवाल में क्यों नहीं बोलूं? ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम: चेयरमैन सर, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप क्यों जवाब दे रहे हैं , मिनिस्टर हैं ना। वे जवाब दे देंगे। ... (व्यवधान)... ठीक है, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... अब आप यह बता दीजिए ...(व्यवधान)... एक मिनट। आप बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य आप बैठिए। ... (व्यवधान)... आप बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, they had not taken the permission from the Planning Commission. *(Interruptions)*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Who said it? *(Interruptions)* Don't say this. The Planning Commission has given permission in principle. *(Interruptions)*

श्री नीलोत्पल बसु: आप जिस तरह से बोल रही हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, he is not the Minister. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. *(Interruptions)* बैठिए, बैठिए, बोलिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए तो सही। ...(व्यवधान)... एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय आप इतना सा उत्तर दे दीजिए कि आपकी सरकार की मंशा इन 6 एम्स को जहां-जहां आपने जगह निर्धारित की है, वहां पर खोलने की मंशा है या नहीं?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Yes, Sir. I totally understand the concern of all the hon. Members. The six new AIIMS have been proposed in very

deserved areas, which are under-served, as far as medical services are concerned. Once the EFC comes, we will initiate the process. *(Interruptions)*

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, आप यह बता दीजिए ...(व्यवधान)... यह एक व्यवस्था का प्रश्न है कि मंत्री महोदय से जो सवाल पूछा है उसका उत्तर स्वंय मंत्री महोदय दें या कोई सम्मानित सदस्य उत्तर देंगे? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अभी तक हाउस में जो प्रेक्टिस चली आ रही है, वही चलती रहेगी। ...(व्यवधान)... ठीक, ठीक है, मैं रोकूंगा?

Task force report on micro irrigation

*65. SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that task force on micro irrigation has submitted its report;

(b) whether it is also a fact that the task force has recommended for an allocation of Rs. 10,500 crores in the Tenth Plan and Rs. 51,000 crores in the Eleventh Plan to meet the needs of three million hectares of micro irrigational needs of the country;

(c) if so, whether Government have studied the report;

(d) whether the matter has been discussed with the Finance Minister and the Planning Commission; and

(e) if so, the outcome of the discussions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI KANTI LAL BHURIA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) A Task Force on Micro Irrigation constituted in 2003 under the chairmanship of the then Chief Minister, Andhra Pradesh has submitted its report to the Central Government. The Task Force has recommended coverage of 3 million ha. under micro irrigation in the country during the Tenth Plan and another 14 million ha. during the Eleventh Plan. According to the Task Force this would require an investment of Rs. 10,500 crores during the Tenth Plan and another Rs. 51,000 crores during the Eleventh Plan.